(ड़) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी योजनाएं कार्यान्वित करने हेतु कितनी सहायता उपलब्ध करवाई गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया हैं पिछले कुछ वर्षों के दौरान राज्य में सूखे की स्थिति बनी रही । राज्य सरकार ने जांच की थी तो यह सुनिश्चित किया था कि इस प्रकार से घटित मृत्यु की घटनायें भुखमरी के कारण नहीं हुई ।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया हैं कि वर्ष 1996 के दौरान 28 जिलों में 28837 गांव तथा 1997 के दौरान 16 जिलों में 4688 गांव सूखे से प्रभावित हुये । वर्ष 1998 के दौरान प्रारम्भिक रिपोर्ट के अनुसार 24 जिलों में 11192 गांवों तथा 62 वाड़ो में 50% या इससे अधिक फसल हानि होने की सूचना मिली हैं ।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया हैं कि सूखे कि स्थिति का आकलन करने के लिए केन्द्रीय दलों ने दिसम्बर, 1996 तथा अक्तूबर, 1998 में राज्य का दौरान किया था । एक अन्य केन्द्रीय दल ने बोलांगीर तथा सोनीपुर जिलों में कथित भुखमरी से मृत्यु के मामलों की जांच करने के लिए दिसम्बर, 1998 में इन जिलों का दौरा किया था ।

(घ) कालाहांडी-बोलांगीर-कोरापुट जिलों में स्थायी समाधान के लिये उपाय के तौर पर एक दीर्घकालीन कार्य-योजना तैयार की गई हैं । आपातकालीन अहार कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय सहायता दी गई हैं । राज्य ने वृद्ध पेंशन योजना, विशेष पोषण कार्यक्रम, मध्य-दिवस अहार कार्यक्रम, केयर फीडिंग के तहत लाभानुभोगियों की संख्या में वृद्धि की हैं । जल जमाव की संरचनाओं का निर्माण, डीजल पम्पसेंटों की आपूर्ति, पेय जल की समस्या को हल करने के लिये सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में ट्यूब वेल तथा सिंचाई व पेय जल के उद्देश्यों के लिये गहर ट्यूब वेल तथा नये एल0 आई0 पाइन्ट की स्थापना करने के लिये भी योजनाओं तैयार की गई हैं ।

(ड़) 1996-97 के दौरान सूखे की स्थिति में आपदा राहत कोष के तहत वार्षिक आबंटन के अलावा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 50 करोड़ रु0 की सहायता तथा 1997-98 के दौरान आपातकालीन अहार कार्यक्रम के लिये राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 4.00 करोड़ रु0 की सहायता दी गई थी । राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 445.59 करोड़ रु0 की सहायता के संबंध में राज्य सरकार के अनुरोध पर स्थापित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जा रहा हैं ।

New Agricultural Policy

1710. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have finalised a new agricultural policy;

(b) if so, what are the details in terms of redeeming features and new infrastructure institutional network proposed/exist-ing network to be strengthened/upgraded, State-wise; -and

(c) details of action plan proposed by the Agricultural and Processed Foods Export Development Authority (APEDA) under New agricultural policy with reference to Maharashtra in particular?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) and (b) The draft National Policy on Agricultur is in the final stages of drafting.

(c) The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority proposes to set up (i) cold storage and cargo handling facility at Mumbai Airport; and (ii) wholesale market cum Miction centre for flowers in Mumbai.

Post of ESA in Department of Agriculture and Cooperation

1711. SHRI CO. POULOSE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the post of Economic and Statistical Adviser (ESA) of the Department of Agriculture and Cooperation was advertised long back;

(b) whether the present incumbent of the post of Economic and Statistical Adviser (ESA) has already got two extensions, after completion of five years terms;

(c) whether giving extension after six years on a deputation post is against Department of Personnel and Training (DoPT) rules; and

(d) whether the deputation of ESA will be terminated after six years; if not the reasons therefor and the details thereof?